

प्रेषक,
भारकरानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक २५ सितम्बर, 2013

विषय:—जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में न्यायालय भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को कुल 0.270 है 0 निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-230/जिला भूमि व्यव-2013 दि-0-29. 06.2013 द्वे दंदमूर्म में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में न्यायालय भवन निर्माण हेतु पूर्व में शासनादेश सं0-477 / 18(2) / 11-18(96) / 2010 दि-0-21.02.2011 द्वारा हस्तान्तरित कुल 0.482 है 0 भूमि के अतिरिक्त ग्राम सलेमपुर बक्काल में खसरा सं0-99 रकबा 0.067 है 0, 100/1, रकबा 0.067 है 0, 100/2 रकबा 0.068 है 0 एवं 100/3 रकबा 0.068 है 0 इस प्रकार कुल रकबा 0.270 है 0 ग्राम समाज की भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अधीन तथा न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के कम में जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में न्यायालय भवन निर्माण हेतु न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

(7) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) प्रश्नगत जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जर्मीदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०) / (सी) संख्या-3109 / 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-1 से 9 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

प०प०संख्या-२६३५ / समदिनांकित / २०१३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4— निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

